

दिनांक 12 सितम्बर, 1985

सं.ओ.वि./एफ.डी./133-85/37729.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं फरीदाबाद फाऊण्डरी प्लाट नं. 303, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के धमिक श्री विवेनी प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई आद्योगिक विवाद है;

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए, ग्रन्त, ग्रान्डोग्रामिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (म) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-थम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-थम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित थम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निषेध एवं पंचाट तो; माप में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री विश्वेनी प्रसाद की सेवाओं का समापन व्याघ्रोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह कि राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि./एफ.डी./133-85/37736.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं फरीदाबाद काऊण्डरी, प्लाट नं. 306, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री दुर्गा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, श्रीदीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथवा संबंधित मामला है:—

व्या श्री दुर्गा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो.वि./ए.फ.डी./133-85/37743.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं फरीदाबाद फ़ाउण्डरी प्लाट नं. 306, सेच्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मुख लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्धोगिक विवाद है:

झोर चंकि द्विरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांधनीय समझते हैं:

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-63/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अधिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है वा विवाद से संसंगत या सम्बन्धित मामला है : —

क्या श्री मख जाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा टीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. श्र.वि.एफ.डी. 133-85/37750.—चूंकि हस्तियाण के राज्यपाल की राय है कि मै. फरीदावाद फाउण्डरी प्लाट नं. 306, सेक्टर 24, फरीदावाद, के अधिक श्री वलवीर शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई आयोगिक विवाद है :

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु विर्द्धिष्ठ करना बांधनीय समझते हैं :

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई प्रभितयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, हारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, करीदांवाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधिकारी संबंधित मामला है।

क्या श्री वलवीर शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हक्कदार है ?